the whole gamut of D.D.A.'s functioning. May I know which other Ministries are involved in that Committee and when the Report of the Committee will be submitted to the Government?

SHRI SIKANDAR BAKHT: The Report of the Committee was due to be submitted on 28th February but they have asked for an extension of three months.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: Which are the other Ministries that are involved?

SHRI SIKANDAR BAKHT: No other Ministry is involved: it is the local Administration the Municipal Corporation of Delhi, the New Delhi Municipal Committee, L & D etc that are involved

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : मंत्री महोदय ने बताया है कि डी० डी० ए० के बारे में जो कमेटी बनाई गई है, उसमें सिर्फ आफिशल्ज को रखा गया है । क्या कोई ऐसी तजवीज नहीं है कि जिन नान-आफिशल्ज का ताल्लुक डी० डी० ए० की वर्किंग से है, उन्हें और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, कार्पोरेशन आदि के इलेक्टिड रिप्रेजेन्टेटिव्ज को भी ऐसी कमेटीज के साथ एसोशिएट किया जाये, ताकि इन की रिपोर्ट्स केवल आफिशल वर्शन बन कर न रह जायें, बल्कि इन की तरफ से ठीक रिपोर्ट्स दी जाय ?

श्री सिकन्दर बख्त : अध्यक्ष महोदय, अगर यह बात इस सवाल से पैदा होती है, तो मैं कुछ अर्ज कर दूं । इट डज नाट फालो फ्राम दिस कवेश्चन एट आल ।

श्री किशोर लाल : इस से पहले भी पिछले पांच साल में डी० डी० ए० के वर्किंग के मुताल्लिक तीन कमेटियां बन चुकी है और वे अपनी रिपोर्ट्स भी सबमिट कर चुकी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी मंत्री या मंत्रालय ने उन रिपोर्ट्स को देखा है और उन्हें पढ़ने के बाद इस नई कमेटी को मुकर्रर करने की जरूरत महसूस हुई है, या उन्हें पढ़ा ही नहीं गया है और फिर एक कमेटी मुकर्रर कर दी गई है और जैसा हाल उन कमेटियों की रिपोर्ट्स का हुआ है, वैसा ही हाल इस रिपोर्ट का भी होगा ?

श्री सिकन्दर बख्त : यह कमेटी बुनियादी तौर पर इस बात को जहन में रख कर बनाई गई है कि दिल्ली में मल्टी-प्लिसिटी आफ एथारिटीज है । आनरेबल मेम्बर का रफरेंस कौन सी कमेटी की तरफ है, यह मेरे लिए समझना मुश्किल है ।

Policy for Appointment of Chief Executives to State Farms Corporation and National Seeds Corporation

*190. SHRI BIRENDRA PRASAD: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to lay a statement showing.

(a) whether Government's Policy is to appoint the Chief Executives in the State Farms Corporation of India and National Seeds Corporation only out of the persons who are either at the verge of retirement or re-employed after retirement;

(b) if so, will it not affect the employment potential of the younger generation who may be competent to hold these posts,

(c) have such posts ever been circulated to the Bureau of Public Enterprises before the appointment to these posts are made; and

(d) what is the policy of Government for recruitment to these top and lower posts in these two organisations

and also to fill these posts in both these organisations from amongst the existing personnel who may be competent to hold such posts?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (d). No, Sir. Appointments to the posts of Chief Executives are made in consultation with the Bureau of Public Enterprises/Public Enterprises Selection Board Appointments to lower posts are made by the Corporations themselves in accordance with their recruitment rules.

श्री वीरेन्द्र प्रसाद : क्या मंत्री महोदय का ध्यान भारत के राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर, 1938 की ओर आकर्षित हुआ है, जिस में आइटम 4 में कहा गया है कि एस० एफ० सी० आई० और एन० एस० सी० के चीफ एक्सीक्यूटिव की तरह जनरल मैनेजर की पोस्ट भी ब्यूरो आफ पब्लिक एण्टरप्राइजिज और पब्लिक एण्टरप्राइजिज सिलेक्शन बोर्ड के साथ सलाह-मशवरा कर के भरी जायगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या एम० एफ० सी० ई० में श्री ए० एस० संधू की जनरल मैनेजर के पद पर बहाली नियमों के अनकूल हुई है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जैसा कि मैंने अर्ज किया है, ब्यूरो आफ़ पब्लिक एण्टरप्राइजिज और पब्लिक एण्टरप्राइजिज सिलेक्शन बोर्ड को रेफर किया जाता है, वे पैनल भेजते है और उस के जरिये से नाम लिये जाते है।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद : मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या श्री संधू की जनरल मैनेजर की पोस्ट पर नियुक्ति इन संस्थाओं की राय ले कर की गई है। क्या ऐसी बात नहीं है कि वह जायंट कमिश्नर, कॉटन के पद पर काम कर रहे हैं और जुलाई के महीने में रिटायर होने जा रहे हैं? तो क्या यह उन के रिटायर होने के बाद उन्हें फिर से नियुक्त करने की साजिश नहीं है ?

MR. SPEAKER: He has answered that.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: The post is presently filled up on *ad hoc* basis and the Joint Commissioner, Cotton, in the Ministry is holding additional charge of the General Manager from 30th August 1977. Action is being taken to appoint a regular Managing Director to be the Chief Executive.

SHRI C. N. VISVANATHAN: In my constituency, the State Farms Corporation has incurred a loss of Rs. 1.5 crores Whether this Ministry has taken.

MR SPEAKER: This question relates only to the appointment of the chief executive. It does not arise out of this question.

SHRI C N VISVANATHAN: Is the hon Minister aware and is he going to have new irrigation programme in the State Farms and whether they are going to give the State Farms to the Tamil Nadu Government?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: I need a notice for this.

SHRI K. LAKKAPPA: This question relates to the policy for appointment of the Chief Executive of the Corporations. For the last one year, the entire organizational set up and Government machinery for running of the State Farms Corporation and the National Seeds Corporation is completely in shambles. As a consequence, no work has been done by the bureaucrats, and the supply of seeds has not been made to the farmers satisfactorily and the whole thing is in a dilapidated condition. When is Government going to take a realistic view of the whole situation and set

matters right and see that a probe is instituted regarding recruitment system and policy? Will you kmdly assure the House that the organizational set-up would be controlled not by the bureaucrats but by the non-officials and the distribution system of the seeds by the Seeds Corporation and the State Farms would be streamlined?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA So far as the supply of seeds is concerned probably this year the position has been very satisfactory and we have received absolutely no complaints regarding that

SHRI K LAKKAPPA This is not a fact I am myself a farmer and the seeds supplied by the Seeds Corporation did not germinate

The entire organizational set-up and the recruitment and promotion policy of these Corporations is in shambles Will you kindly have a probe in the matter?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA The recruitment is done according to the Articles of Association of these two organizations

श्री राम विलास पासवान अध्यक्ष जी, इस के पहले के सत्र मे जब राष्ट्रीय बीज निगम के सम्बन्ध म प्रश्न का उत्तर दिया गया था तो बताया गया था कि इस निगम में ज्वाइन मेनेजर से चौकीदार तक जो पद है उन मे हरिजनो और आदिवासियों की सख्या नगण्य है तो क्या अभी यही स्थिति चल रही है ? जो जानकारी हमे मिलती है या हमारे पास आवेदन-पत्र आते है उन से पता लगता है कि इन वर्गों के लोगो की सीनियर होने और उनमे योग्यता होने के बावजद अवहेलना की जाती है । लेकिन सरकार की तरफ से हमेशा यही कहा जाता है कि इन वर्गों के प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाएगा । मै मत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब कोई नियुक्ति होती है या किसी पद पर प्रमोशन होती है तो क्या वे स्वय यह देखते है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग उस पद के लिए उपलब्ध है या नही या ऐसे ही उनके आवेदन-पत्रो को एक तरफ कर दिया जाता है जिससे उन पर कोई कार्यवाही न हो सके ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : स्वय तो जानकारी हासिल नही की जा सकती है । लेकिन डिपार्टमेंट को यह कहा हुआ है कि पिछड़ी जाति और शेडयल्ड कास्ट्स के लोगो का पूरा ध्यान रखा जाए । अगर किसी जगह उनका रिप्रेजेन्टेशन पूरा नही है और माननीय सदस्य मुझे बताये तो उस को देखा जाएगा ।

Self Financing Housing Scheme of DDA

*193 SHRI KANWAR LAL GUPTA Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state

(a) whether the response to DDA s new Self Financing Scheme for a house by depositing the amount of Rs 10 000/ is not encouraging

(b) how many persons have deposited the money so far,

(c) what is the detailed scheme of DDA to construct 40 000 tenements in a year in Delhi,

(d) what are the relaxations which DDA/Government propose to make to encourage housing in Delhi

(e) have Government allowed private agencies to go for housing in Delhi, and

(f) will Government allow the new housing co-operative societies to build houses in the Capital?